Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding sharing of information regarding expenditure and programmes under CSR funds in aspirational districts particularly in Gaya disrict, Bihar-Laid.

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम की जनवरी, 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरूआत की गई थी। इसका उद्देश्य देश के अपेक्षाकृत कम विकसित 112 जिलों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार लाना है । यह सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मार्ग दर्शक सिद्धांत के माध्यम से 2020-22 के नये भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है ।

भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक उद्यम विभाग आकांक्षी जिलों में विकास के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में के कारपोरेट सामाजिक दायित्व का कार्यक्रम चला रहा है । नीति आयोग 12 आकांक्षी जिलों में हितकारकों के साथ काम कर रहा है ।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने दिशानिर्देश जारी किये थे कि वे आकांक्षी जिलों के उल्लेख के साथ प्रतिवर्ष एक खास विषय पर अपनी सीएसआर निधियों का 60 प्रतिशत खर्च करे। हर वर्ष सीपीएसआई का औसत सीआर खर्च 3500 करोड़ रूपये है और इस कार्य का 60 प्रतिशत 2100 करोड़ रूपये के बराबर है । यह रकम आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य, पोषण और स्कूली शिक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है । मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद में गया जिले का अतरी विधान सभा क्षेत्र आता है जिसमें चार प्रखंड हैं। गया जिला का अतरी विधान सभा क्षेत्र आता है जिस में चार प्रखंड हैं । गया जिला एक आकांक्षी जिला घोषित है। मेरा सरकार से आग्रह है कि क्षेत्र के जन-प्रतिनिधियों को कार्यक्रम की पूरी जानकारी (जैसे खर्चों का ब्यौरा, कार्यक्रम के नाम, दान-दाताओं के नाम इत्यादि) दी जाए ।